



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 20 जनवरी, 2022/30 पौष, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 05 जनवरी, 2022

संख्या राजस्व-घ/(एफ) 4-8/2019-लूज (कुल्लू).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील जरी सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गावों के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

सके और जिससे उनको होने वाली किसी असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हो सके;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश तहसील भून्तर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्न स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए सात पटवार वृत्तों से गठित एक नई उप-तहसील जरी, जिसका मुख्यालय जरी में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं :-

उप-तहसील का नाम	मुख्यालय	वर्तमान तहसील भून्तर में सम्मिलित पटवार वृत्तों के नाम	उप-मण्डल का नाम	जिला	नई उप-तहसील में सम्मिलित किए जाने वाले पटवार वृत्त
1	2	3	4	5	6
जरी	जरी	मौहल खोखन बजौरा रोट-II गड़सा पारली मंझली दियार शिलीहार चौंग शाट कशावरी पीणी जरी बराधा सोसन मनीकर्ण	कुल्लू	कुल्लू	चौंग शाट जरी बराधा सोसन मनीकर्ण पीणी

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा,
प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D(F)4-8/2019-Loose (Kullu), dated 5th January, 2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 05th January, 2022

No. Rev-D(F) 4-8/2019-Loose (Kullu).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to create a new Sub-

Tehsil Jari in District Kullu, Himachal Pradesh, so as to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid any inconvenience being faced by them and to have better administrative control;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub- Tehsil Jari in District Kullu, Himachal Pradesh, consisting of 7 Patwar Circles shown in column No.6 below, with immediate effect:—

Name of the Sub-Tehsil	Head quarter	Name of Patwar Circles presently included in Bhunter	Name of Sub-Division	District	Patwar Circle to be included in new Sub-Tehsil
1	2	3	4	5	6
Jari	Jari	Mohal Khokhan Bajora Rot-II Gadsa Parli Manjhli Diyar Shillihar Chong Shat Kashawri Peeni Jari Baradha Sosan Manikaran	Kullu	Kullu	Chong Shat Jari Varadha Sosan Manikaran Peeni

By order,

ONKAR CHAND SHARMA
Principal Secretary-cum-FC (Revenue).

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 07 जनवरी, 2022

संख्या:राजस्व-घ (ए)1-11/2021(चम्बा).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि उप-तहसील होली, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश का दर्जा बढ़ाकर तहसील कर दिया जाए जिसका मुख्यालय होली, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में होगा ताकि नजदीक के गावों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली किसी असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हो सके;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित पटवार वृत्तों से समाविष्ट उप-तहसील होली, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश का दर्जा बढ़ाकर तहसील का करते हैं :-

तहसील का नाम	मुख्यालय	उप-मण्डल का नाम	जिला	सम्मिलित पटवार वृत्त
1	2	3	4	5
होली	होली	भरमौर	चम्बा	1. बजोल 2. घडौ 3. दियोल 4. होली 5. तियारी 6. कुठेहड़ 7. साह 8. क्वारसी 9. चन्हौता 10. गरोला

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा,
प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D(A)1-11/2021-(CBA) dated 07-01-2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 07th January, 2022

No.Rev-D(A) 1-11/2021-(CBA).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to upgrade the status of Sub-Tehsil Holi, District Chamba, Himachal Pradesh to that of Tehsil with its Headquarter at Holi,

District Chamba, Himachal Pradesh, so as to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid any inconvenience being faced by them and to have a better administrative control;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to upgrade the status of Sub-Tehsil Holi to that of Tehsil in District Chamba, Himachal Pradesh, consisting of following Patwar circles:—

Name of the Tehsil	Headquarter	Name of Sub-Division	District	Patwar Circles Included
1	2	3	4	5
Holi	Holi	Bharmour	Chamba	1. Bajol 2. Ghado 3. Diol 4. Holi 5. Tiary 6. Kuther 7. Sah 8. Kwarsi 9. Chanhota 10. Garola

By order,

ONKAR CHAND SHARMA
Principal Secretary-cum-FC (Revenue).

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 05 जनवरी, 2022

संख्या: राजस्व-घ/(एफ)4-7/2020-(कुल्लू).—हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.17 एवम् 3.18 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश तहसील

मनाली, जिला कुल्लू के अन्तर्गत पटवार वृत्त बुरुआ, वशिष्ठ, प्रीणी, जगतसुख, वर्शाई, बड़ागांव, बरान तथा मनाली का विघटन करके 6 नये पटवार वृत्त पलचान, खखनाल, पत्तिकुहल, शाल्लिन, मनुनगर और कन्यालत तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का अनुबन्ध 'क' में दिये गए विवरण अनुसार खोलने का सहर्ष आदेश देते हैं। इन पटवार वृत्त हेतु एक पद पटवारी वेतनमान मु0 5910-20,200+1900 ग्रेड पे, मांग संख्या: 5, मुख्यशीर्ष-2029-00-103-04 (गैर-योजना) एवं एक पद अंशकालिक कार्यकर्ता (Part time worker) का सृजन/भरने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। नये पटवार वृत्तों के सृजन उपरान्त विद्यमान पटवार वृत्तों की वर्तमान स्थिति अनुबन्ध 'ख' अनुसार होगी।

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा,
प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

अनुबन्ध 'क'

नये सृजित पटवार वृत्त पलचान, खखनाल, पत्तिकुहल, मनुनगर, शाल्लिन तथा कन्यालत की स्थिति का विवरण:-

क्रम संख्या	पटवार वृत्त	राजस्व ग्राम	कुल क्षेत्र है0	कृष्य क्षेत्र	कुल खसरा नं0	कुल खतौनी	जनसंख्या
1.	पलचान	सोलंग			801	117	1118
		पलचान	163-17-88	04-83-00	1597	285	1502
		कोठी	239-05-13	12-33-00	761	89	384
		कुलांग	79-70-28	02-74-00	599	93	316
	जोड़..		481-93-29	14-73-00	3758	584	3320
2.	खखनाल	कलौंज	95-19-56	00-01-12	42	22	188
		खखनाल	105-09-54	63-62	1466	467	722
		गोजरा	49-16-37	41-72	1086	397	574
		सजला	107-86-14	89-35	1962	624	684
		सजला विहाल	24-98-31	12-83-00	156	58	221
		वरनाड़	100-60-42	003-28-00	167	89	88
	जोड़..		482-90-34	211-92	4879	1657	2477
3.	पत्तिकुहल	बादी	180-03-04	69-23	1826	657	2310
		हलान-2	232-32-40	35-82	1116	449	333
		मगाना	128-60-14	24-67	969	194	233
		शिला	215-22-93	75-25	957	192	326
		तराशी	203-85-42	67-30	845	144	343
	जोड़..		960-03-93	272-27	5713	1636	3545

4.	मनुनगर	मनाली सेर	53-40-86	29-26	630	238	47
		मनाली	48-30-85	24-44	1073	238	914
		मनाली कूट	53-40-86	0	670	49	6
		तयान पधर	64-87-56	14-72	232	90	33
		मनुनगर	77-54-87	21-24	629	209	825
		कालीगांच	61-24-83	14-98	278	94	132
		डुगारी प्रथम	23-90-47	10-49-00	809	167	55
		डुगारी द्वितीय	5-72-03	03-79-00	180	37	329
		आरक्षित वन आर-I	14-50-41	0	17	1	0
		आरक्षित वन आर-II	21-51-66	0	13	1	0
		आरक्षित वन आर-III	10-17-44	0	40	1	0
	जोड़..		434-61-84	118-92	4571	1125	2341
5.	शाल्लिन	परशा	96-00-19	48-48	1449	319	772
		शाल्लिन	89-62-39	47-11	1540	342	411
		गधेरनी	53-89-03	36-32	1092	374	1159
		कलोनट	39-67-49	16-36	205	55	14
		झुन्जरी	001-20-07	0	4	4	7
	जोड़..		280-39-17	148-27	4290	1094	2363
6.	कन्यालत	सिमसा	68-12-24	50-12	1429	427	615
		कन्याल	79-86-29	37-40	627	241	363
		छियाल	42-61-37	30-47	816	300	606
		नसोगी	34-19-43	27-05	1058	251	790
	जोड़..		224-79-33	145-04	3930	1219	2374

अनुबन्ध 'ख'

नये पटवार वृत्तों के सृजन उपरान्त वर्तमान पटवार वृत्त बुरुआ, वशिष्ठ, प्रीणी, जगतसुख, वर्राई, बड़ागांव, पंगान, बरान, मनाली की स्थिति निम्न प्रकार होगी :-

क्रम संख्या	पटवार वृत्त	राजस्व ग्राम	कुल क्षेत्र हैक्ट0	कृष्य क्षेत्र	कुल खसरा नं0	कुल खतौनी	जनसंख्या
1.	बरुआ	बुरुआ	203-11-47	136-76	1773	484	1423
		मझाच	126-42-00	39-38	1179	382	481
		शनाग	165-50-86	28-56	2185	516	935

		गोशाल	106-42-11	27-46	1400	294	905
		बहनग	128-01-79	22-88	610	245	1724
		डीपीएफ व्यास टिब्बा	1-62-08	0	1	1	0
		बुरुआ मझाच	249-55-94	89-13	2235	386	532
	जोड़..		980-69-25	344-17	9383	2308	6000
2.	वशिष्ठ	वशिष्ठ	110-82-75	59-31-00	1183	337	1789
		कौशला	86-42-25	45-77-00	1200	254	997
		धरानु	59-25-67	03-47-00	941	234	1255
		चचोगा	33-63-14	20-20-00	1333	343	1382
		अलेऊ	124-25-91	69-08-00	2131	499	1788
		डीपीएफ अलेऊ विहाल	26-70-16	0	5	1	111
	जोड़..		441-09-88	197-83	6793	1668	7322
3.	प्रीणी	शुरू	144-97-48	103-88	3294	835	1333
		प्रीणी	92-66-00	62-37	1824	469	1057
		हमटा	93-98-42	21-67	391	106	108
		जमादी	103-03-49	35-53	462	75	9
		हमटा 2 / 17	384-69-96	21-71	223	29	31
		हमटा 1 / 7	004-20-94	18-81	223	4	65
	जोड़..		823-56-29	263-97	6417	1518	2603
4.	जगतसुख	जगतसुख	173-30-90	127-93	3252	1084	1891
		छनाला	125-34-16	70-71	1405	414	210
		वहनू	34-83-94	19-71-00	579	129	187
		भनारा	163-05-62	30-47	484	166	381
	जोड़..		496-64-62	248-82	5720	1793	2669
5.	वर्शाई	कर्जन	154-79-62	123-30	2441	654	1319
		सोयल	126-50-21	101-46	1976	515	1158
		हरिपुर	161-67-23	118-05	1898	620	886
		सोमवन	28-43-53	0	6	3	54
	जोड़..		471-40-59	342-81	6321	1792	3417
6.	पंगान	पंगान	128-52-74	73-54	1827	421	662
		डफरी	127-85-94	58-24	1307	226	427
		गुमिधार	44-29-05	28-21	638	180	477
		रियादा	122-24-31	47-33	912	319	475
		शंघचार	119-92-43	54-67	1521	446	767
		छदोगी	119-29-50	15-18	263	90	1

		मंदरोन	85-65-98	00-02-04	128	60	0
	जोड़..		747-79-95	279-21	6596	1742	2809
7.	बड़ागांव	बड़ागांव	332-07-26	145-82	3017	657	1948
		नयालग	118-83-14	41-10	779	143	241
		शेगली	266-33-16	40-20	1128	142	150
		कषेरी	227-34-83	00-12-95	662	106	139
	जोड़..		944-58-39	240-07	5586	1048	2478
8.	बरान	बरान	187-48-09	46-93	1225	368	611
		दोभा	152-82-36	59-86	1391	412	495
		रामपुर	74-34-59	52-48	1299	443	444
		कलथ	148-45-88	29-73	951	211	668
	जोड़..		563-58-92	189-00	4866	1434	2218
9.	मनाली	कस्वाती नसोगी	32-78-15	003-16-00	3837	454	4764
		अरक्षित वन आर-4	33-35-12	0	165	2	0
		सियाल	38-97-81	29-81	1449	398	2345
		भजोगी	38-67-99	10-44-00	1515	402	1142
		कस्वाती छियाल बिहाल	18-23-06	02-33-00	275	24	88
	जोड़..		162-02-13	45-74	7241	1280	8339

**OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER MUNICIPAL COUNCIL, JOGINDER NAGAR
DISTT. MANDI (H.P.)**

NOTIFICATION

Dated, the 4th January, 2022

No. MCJNR-2022-21.—The following Bye-laws made by Municipal Council **Joginder Nagar, Distt. Mandi (H.P.)**, for regulating The **Door-to-Door Garbage Collection & Disposal-2018** in exercise of the powers conferred by section 202 and 217 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) read with rule 15 (zf) of the Solid Waste Management Rules, 2016 having been confirmed by State enforcement, as required under section 217 of the aforesaid Acts are here by published for general information, namely:—

**BYE LAWS TO REGULATE DOOR-TO-DOOR GARBAGE COLLECTION & DISPOSAL
OF MUNICIPAL COUNCIL JOGINDER NAGAR
DISTT. MANDI (H.P.)**

GENERAL

1. Short title and commencement.—(a) These bye-laws may be called The Door-to-Door Garbage Collection and Disposal Bye-laws-2018 of Municipal Council Joginder Nagar for municipal solid waste management & disposal.

(b) These Byes-laws shall come into force on the date of their adoption.

(c) This shall apply to Joginder Nagar Municipal area.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires.—

(A) **“Act”** means the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act 1994 and Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

(B) **“bulk waste generator”** means and includes buildings occupied by the Central Government Departments or Undertakings, State Government Departments or undertakings, local bodies, public sector undertakings or private companies, hospitals, nursing homes, schools, colleges, universities, other educational institutions, hostels, hotels, commercial establishments, markets, places of worship, stadia and sports complexes having an average waste generation rate exceeding 100 kg per day;

(C) **“bye-laws”** means regulatory framework notified by local body, census town and notified area townships for facilitating the implementation of these rules effectively in their jurisdiction.

(D) **“composting”** means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter;

(E) **“disposal”** means the final and safe disposal of post processed residual solid waste and inert street sweepings and silt from surface drains on land as specified in Schedule I to prevent contamination of ground water, surface water, ambient air and attraction of animals or birds;

(F) **“domestic hazardous waste”** means discarded paint drums, pesticide cans, CFL bulbs, tube lights, expired medicines, broken mercury thermometers, used batteries, used needles and syringes and contaminated gauge, etc., generated at the household level;

(G) **“door-to-door garbage collection”** means collection of solid waste from the door step of households, shops, commercial establishments, offices, institutional or any other non-residential premises and includes collection of such waste from entry gate or a designated location on the ground floor in a housing society, multi storied building or apartments, large residential, commercial or institutional complex or premises;

(H) **“dry waste”** means waste other than bio-degradable waste and inert street sweepings and includes recyclable and non-recyclable waste, combustible waste and sanitary napkin and diapers, etc;

(I) **“dump sites”** means a land utilised by local body for disposal of solid waste without following the principles of sanitary land filling;

- (J) **"fine/penalty"** means penalty imposed on waste generators or operators of waste processing and disposal facilities under the bye-laws for non-compliance of the directions contained in these or bye-laws;
- (K) **"municipality"** means the municipal Council / Nagar Panchayat of Himachal Pradesh;
- (L) **"non-biodegradable waste"** means any waste that cannot be degraded by microorganisms into simpler stable compounds;
- (M) **"sanitary land filling"** means the final and safe disposal of residual solid waste and inert wastes on land in a facility designed with protective measures against pollution of ground water, surface water and fugitive air dust, wind-blown litter, bad odour, fire hazard, animal menace, bird menace, pests or rodents, greenhouse gas emissions, persistent organic pollutants slope instability and erosion;
- (N) **"sanitary waste"** means wastes comprising of used diapers, sanitary towels or napkins, tampons, condoms, incontinence sheets and any other similar waste;
- (O) **"schedule"** means the schedule indicating the rate in respect of sign boards;
- (P) **"secondary storage"** means the temporary containment of solid waste after collection at secondary waste storage depots or MRFs or bins for onward transportation of the waste to the processing or disposal facility;
- (Q) **"segregation"** means sorting and separate storage of various components of solid waste namely biodegradable wastes including agriculture and dairy waste, non-biodegradable wastes including recyclable waste, non recyclable combustible waste, sanitary waste and non-recyclable inert waste, domestic hazardous wastes, and construction and demolition wastes;
- (R) **"service provider"** means an authority providing public utility services like water, sewerage, electricity, telephone, roads, drainage, etc;
- (S) **"user fee/ charge"** means a fee imposed by the local body and any entity mentioned in rule on the waste generator to cover full or part cost of providing solid waste collection, transportation, processing and disposal services.
- (T) **"waste picker/ collector"** means a person or groups of persons informally engaged in collection and recovery of reusable and recyclable solid waste from the source of waste generation the streets, bins, material recovery facilities, processing and waste disposal facilities for sale to recyclers directly or through intermediaries to earn their livelihood.

Words and expressions used herein but not defined, but defined in the Environment (Protection) Act, 1986, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, Himachal Pradesh Corporation Act, 1994, Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and Solid Waste Management Rules, 2016 shall have the same meaning as assigned to them in the respective Acts and Rules.

CHAPTER—II

MANAGEMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE

3. Municipal Solid Waste Management.—The Municipal Council/Nagar Panchayat shall establish an integrated Solid Waste Management (SWM) system with an aim to reduce the amount of waste being disposed, while maximizing resources recovery and efficiency. The preferred waste management system shall focus on the following points, namely:—

- I. Reduction and reuse at source.**—The most preferred option for Solid Waste Management shall be prevention of waste generation. It will be helpful in reducing the handling, treatment, and disposal costs and specially reduce various environmental impacts such as leachate, air emissions and generation of greenhouse gases.
- II. Waste recycling.**—Recovery of recyclable material resources through a process of segregation, collection and re-processing to create new products shall be the next preferred alternative.
- III. Composting.**—As far as possible the organic fraction of waste shall be composted and used to improve soil health and agricultural production adhering to norms.
- IV. Waste-to-Energy.**—Where material recovery from waste is not possible, energy recovery from waste through production of heat, electricity or fuel may be preferred. Bio-methanation, waste incineration, production of Refuse Derived Fuel (RDF) and co-processing of the sorted dry rejects from municipal solid waste are to be commonly adopted “Waste to Energy” technologies.
- V. Waste disposal.**—Remaining residual waste, which ideally comprises of inserts, shall be disposed in sanitary landfills constructed in accordance with stipulations of the Solid Waste Management Rules, 2016.
- VI.** The Integrated Solid Waste Management system shall be environment friendly. Waste minimization, waste recycling, waste-to-energy strategies and landfill gas capture and use which are promoted in the Solid Waste Management Rules, 2016 shall be adopted for reduction of greenhouse gases.

CHAPTER—III

MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION & TRANSPORTATION

4. Segregation & Primary Storage of Municipal Solid waste:—

- (a) It will be prime responsibility of every waste generator/citizen to segregate the waste generated by them in three separate streams namely bio-degradable, non-biodegradable and domestic hazardous wastes in suitable covered bins and handover segregated wastes to authorised waste pickers or waste collectors designated by ULBs or Agency Hired by ULBs once a day or at the frequency as decided by respective local body on the timing fixed by the service provider. Every citizen has to pay a fixed monthly rental for the services of door-to-door garbage collection.
- (b) Waste generators shall be encouraged to segregate waste and store at source in three separate colour bins *i.e.* green-for biodegradable waste, blue-for non-biodegradable, red-for domestic hazardous waste.

-
- (c) All institutions with more than 5,000 sqm area shall, within one year from the date of notification of these bye-laws and in partnership with the Municipal Council/Nagar Panchayat, ensure segregation of waste at source by the generators, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the Municipal Council/Nagar Panchayat.
- (d) No person shall organise an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating the Municipal Council/Nagar Panchayat, at least three working days in advance and such person or the organiser of such event shall ensure segregation of waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency as specified by the Municipal Council/Nagar Panchayat.
- (e) Used sanitary waste are to be securely wrapped as and when generated in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a newspaper or suitable biodegradable wrapping material and place the same in the bin meant for non-biodegradable waste or dry waste.
- (f) Every street vendor shall keep suitable containers for storage of waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover food, vegetables, fruits, etc., and shall deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by the Municipality.
- (g) Store separately construction and demolition waste, as and when generated, in his own premises and shall dispose off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
- (h) Bulk waste generators of garden and horticulture waste like park, stadium etc. shall store separately in their premises and dispose of the same as may be prescribed by the Municipal Council/Nagar Panchayat from time to time.
- (i) No untreated bio-medical waste, e-waste, hazardous chemicals and industrial waste shall be mixed with municipal solid waste and such waste shall follow the rules specifically separately specified for the purpose.
- (j) Every waste generator has to ensure that there is no practice of burning or burying the solid waste generated by him, throwing on streets/ open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies.
- (k) Littering of waste on streets /open space/ water bodies /drain shall be fined on the spot. On iterate they will be punishable and can subjected to court as per rule.
- (l) Time to time awareness generation campaigns should be organised to motivate people. RWA (Resident Welfare Association), Local NGOs, representative of public association and elected local member should be involved in the programme to motivate citizen.

5. Primary Collection of Municipal Solid Waste.—(a) Each and every house in the city/ town should approached for the primary collection of waste by means of wheel barrow, push cart, tricycle, small auto tipper depending on the size of road available.

(b) Municipal Council Joginder Nagar have to arrange for daily door-to-door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non-residential premises. From multi-storage buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes, etc., this may be collected from the entry gate or any other designate location;

(c) Municipal Council Joginder Nagar have to establish a system to recognise organisations of waste pickers or informal waste collectors and promote and establish a system for integration of these authorised waste-pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door-to-door collection of waste;

(d) Municipal Council Joginder Nagar have to facilitate formation of Self Help Groups, provide identity cards and thereafter encourage integration of informal waste pickers in solid waste management including door-to-door collection of waste.

(e) Municipal Council Joginder Nagar have to collect separately waste from sweeping of streets, lanes and by-lanes daily, or on alternate days or twice a week depending on the density of population, commercial activity and local situation.

(f) Municipal Council Joginder Nagar have to collect horticulture, parks and garden waste separately and process in the parks and gardens, as far as possible.

(g) Time for the door-to-door collection services will have to fixed by the concern ULBs. Generally timing should to be between 6.00 AM to 9.00 AM. For proper waste collection vehicle such as tricycle, auto tipper used for door-to-door garbage collection should be equipped with Alarm with audible decibel fixed as per the rules and timing should be strictly followed by the sanitation workers.

(h) For door-to-door garbage collection from commercial complex, offices and secondary bins timing should be between 9.00 AM to 11.00 AM.

(i) For proper solid waste management & grievance redress Municipal Council Joginder Nagar should set up small office/ centre in each ward of their boundaries.

(j) Under door-to-door services user charge for collection should be formulated on the following criteria.

Sl. No.	Category of User	User Charge on monthly basis (INR)
1.	Household (area less than 2000 sq. feet)	50
2.	Household (area more than 2000 sq. feet)	100
3.	Commercial Complex (Dhabba, sweet shop, coffee houses, provisional stores) .	350
4.	Pan Shop	80

5.	Tea Shop	80
6.	Shops (Daily needs, cloths)	100
7.	Vegetables & fruits shops (Wholesale)	1000
8.	Vegetables & fruits shops (Retails)	250
9.	Sweet/snacks shop (Big)	400
10.	Offices (2 rooms)	100
11.	Offices (3-5 rooms)	250
12.	Offices (6-10 rooms)	1000
13.	Offices (11-20 rooms)	2000
14.	Offices (more than 20 rooms)	2000 for 20 rooms + 100 per additional room.
15.	Bank	500
	Bank Floor Area > 1000 sq. feet	750
16.	Govt. Schools	100
17.	Private Schools upto 100 students on producing student's enrolment certificate.	500
18.	Private Schools (more than 100 students)	1500
19.	Bakeries (small)	500
20.	Bakeries (manufacturing units)	1200
21.	PG Hostel / Guest House (upto 10 rooms)	500
22.	PG Hostel / Guest House (11-20 rooms)	1500
23.	PG Hostel / Guest House (21-30 rooms)	2500
24.	PG Hostel / Guest House (more 30 rooms)	2500 for 30 rooms+500 per additional room.
25.	Dharamsala	550
26.	Factories (Manufacturing unit) other than notified in any other category	1500
27.	Workshop (Tyre puncture shop)	100

28.	Workshop (repair shop)	250
29.	Workshop (repair + spare parts shop)	500
30.	Workshop (vehicle showroom, repair + spare parts)	750
31.	Workshop (those not touching any NH or SH).	300
32.	Restaurants	1500
33.	Restaurants + Bar	1700
34.	Cinema Hall (Theatre, multiples)	1500
35.	Govt. College	1000
36.	Private College	1500
37.	Hospital /Nursing Home (upto 50 beds)	1500
38.	Hospital /Nursing Home (51-100 beds)	2000
39.	Hospital /Nursing Home (more than 100 beds).	2000 + 250 per additional bed
40.	Clinics	150
41.	Clinics with medicines shops	250
42.	Chemist shop	200
43.	Laboratory	200
44.	Banquet Hall/ Hotel	2000 & 2000 per trip on demand
45.	Special Hotels more than 50 Rooms	15000 & 2000 per trip on demand
46.	Vehicle on demand for Dumper	3000 per trip
47.	Big Malls	2000 per floor
48.	Meat Shops (other than subscribed with chicken waste collection vehicle).	500
49.	Confectionary + Veg Shop	250
50.	Scrap Dealers	400
51.	Street Vendor	100
52.	Cow dung from cattle at households	350
53.	Any other establishment(s) not mentioned above.	To be decided by ULB

Note.—User charge as prescribed above can be revised by the ULB time to time keeping in view the polluter pay principal to meet the operation and maintenance cost of the services under Solid Waste Management.

(k) User charge mentioned above for door-to-door services needs to be collected from each and every household & other establishment of all the wards in the municipal boundaries of the ULBs. Users charge decided above, contact person's name & number needs to be conveyed to general public through different media such as display on the vehicles used for these services, hoardings, pamphlets etc. Also, awareness generation campaigns need to be organised.


(l) No manual loading or unloading of waste in compactor should be practised with open hand or without safety measure as per the Solid Waste Management Rules, 2016.

6. Secondary Storage of Municipal Solid Waste.—Municipality by their own or with help of Agency hired needs to develop storage bins/ secondary storage points for the collection of waste generated in the town, they will also be responsible to monitor the condition of these bins so that no filthy or unhygienic condition develops around. While establishing or monitoring secondary storage bins following precaution needs to be taken care.


(a) Storage/Secondary storage bins should be designed and develop on the basis of the quantity of waste generated, density of population in the notified municipal boundaries. Minimum distance between two bins should be 500 meters and within radius of 1 km maximum numbers of bins should limited upto 5. Established bins must be covered with movable lid and must be approachable/connected with metallic or non-metallic road.

(b) Bins provided by Municipal Council Joginder Nagar or any hired agency should be designed in such a manner so that waste disposed in does not get scattered in open atmosphere and it should be artistic in nature so that it motivates people to dispose their waste in the bins not in open.

(c) Bins placed at designated place by Municipal Council Joginder Nagar or any hired agency should motivate people to practice waste segregation and it should be placed as per Solid Waste Management Rule, 2016 having colour coding for different types of waste.

 Green: - Biodegradable waste (Food waste, garden waste)

 Blue: -Non-Biodegradable waste

 Red: - Hazardous or toxics waste

(d) Well-designed vehicle like auto Tipper/Compactor should be used for the purpose of transportation of waste and evacuating the bins.

(e) All the cooperative society, residential welfare association/society, institutional organisation will be responsible to place suitable quantity of bins approved by the Municipal Council/Nagar Panchayat on the fixed place in their compound so that waste generated from there can be stored properly and collected from time to time by the municipal vehicle. User charge for these services fixed by the ULBs should be collected by the authorised person of local body.

(f) It will be prime responsibility of all the waste generators/citizens to store and sell/handover the recyclable waste to the Rag pickers/Kabadiwala or person/organisation designated by the Municipal Council/Nagar Panchayat. They have to ensure that no such waste is being disposed on the road/ drain / secondary storage bins/ open space.

(g) Door-to-door garbage collection, secondary storage bins, collection & transportation, processing of waste and disposal of waste in sanitary land fill site, all these services will be provided by Municipal Council Joginder Nagar or any hired agency. ULBs will charge user fee for all these services and violator will be fined on the spot or punished and can be subjected to court as per rule.

(h) Waste from the slaughter house, fish market, fruit & vegetable market is biodegradable in nature, so proper storage facility should be designed so that no health hazard spreads from this & facility for composting should be developed to make use of such waste in generating organic manure from it. For ensuring proper disposal of such waste every generator have to ensure best storage facility and segregation of such waste at source and door-to-door collection should be practiced by ULBs to collect 100% of such waste and take to processing plant. On Violation, waste generator should be fined on the spot or punished and can be subjected to court as per rule.

(i) Municipal Council Joginder Nagar have to establish waste deposition centres for domestic hazardous waste and give direction for waste generators to deposit domestic hazardous wastes at this centre for its safe disposal. Such facility shall be established in a city or town in a manner that one centre is set up for the area of twenty square kilometres or part thereof and notify the timings of receiving domestic hazardous waste at such centres.

(j) Bio medical & industrial waste should not be mixed with municipal waste and such waste should be stored and disposed separately as per the rules applicable. For the disposal of bio-medical waste common Biomedical Waste treatment facility (CBMWTF) should be developed in each ULB either separately or on the cluster basis. By paying the fixed user fee such waste can be easily disposed off.

(k) Construction and demolition waste should be stored separately as and when generated, in his/her own premises and shall be disposed off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016. ULBs should fix user charge for transportation and disposal of C&D waste and generator should dispose this waste by paying the charge as per the rules and at the designated place. Disposing of such waste in open space, road side, common place will be treated as illegal and fined as per the rules.

(l) Gardening/Horticultural waste should also be stored separately at source. ULBs should fix a day or two in week and some place where generator should give their waste and from there it should be transported to disposal site.

(m) Dry leaves, plastic and other such waste should not be burnt in open, doing such activity will be treated as illegal and punishable, violator should be fined as per the rules.

(n) Stray animal should be restricted from roaming in and around the waste disposal site & secondary storage bins or any public place in the town.

(o) Every citizen, institutions, office buildings, commercial complexes has to ensure that there is no open discharge of grey water, black water or any other such polluted water in drain, open space or on road which can spread health issues, doing such activity will be treated as illegal and punishable as per the rules.

(p) No person should dispose dead animal or any such material in open space, road side, community park or any other place which can spread pollution and health issues, doing such activity will be treated as illegal and punishable as per the rules.

(q) Municipal Council/Nagar Panchayat have to set up covered secondary storage facility for temporary storage of street sweepings and silt removed from surface drains in cases where direct collection of such waste into transportation vehicle is not convenient. Waste so collected shall be collected and disposed of at regular intervals as decided by the local body.

(r) Municipal Council/Nagar Panchayat can develop bins free solid waste management facility but for this 100% waste collection from the door step of the generator should be ensured.

7. Secondary Collection & Transportation of Municipal Solid Waste:—(a) Each storage bins/secondary storage bins should be attended daily by the help of auto tipper, tractor, compactor etc.

(b) Closed vehicle should be used for the transportation of waste. To reduce the frequency of loading and unloading of waste compactor should be used.

(c) Municipal Council/Nagar Panchayat will have to ensure safe storage and transportation of the domestic hazardous waste to the hazardous waste disposal facility.

(d) Transport segregated bio-degradable waste to the processing facilities like compost plant, bio-methanation plant or any such facility. Preference shall be given for onsite processing of such waste.

(e) Transport non-bio-degradable waste to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility. Ensure transportation of construction and demolition waste as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

CHAPTER—IV

MUNICIPAL SOLID WASTE PROCESSING & DISPOSAL

8. Waste Processing Plant:—Municipal Council Joginder Nagar with help of State Pollution Control Board approval needs to develop solid waste management/processing plant to make use of daily generated biodegradable waste so that it can reduce the quantity of waste being disposed at the sanitary land fill site.

- (a) Municipal Council/Nagar Panchayat have to collect waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market on day-to-day basis and promote setting up of decentralised compost plant or bio-methanation plant at suitable locations in the markets or in the vicinity of markets ensuring hygienic conditions.
- (b) Involve communities in waste management and promotion of home composting, bio-gas generation, decentralised processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygienic conditions around the facility.
- (c) For processing of biodegradable waste Municipal Council / Nagar Panchayat have to establish waste processing plant such as composting plant – windrow compost plant, vermi composting plant, waste to energy or any other such technology by their own or with help of any other licensed company/firm/organisation on Build–operate–Transfer (BOT)/ Object Oriented (OO) method.

- (d) For processing of mixed recyclable waste Municipal Council Joginder Nagar have to establish recycling units such as incineration, RDF Plant or other such recycling technology by their own or with help of any other licensed company/firm /organisation on Build-operate-transfer (BOT)/ Object Oriented (OO) method.
- (e) Municipality may also send the non-biodegradable/dry waste as RDF to nearby cement factories for co-processing.

9. Waste Disposal:—(a) Municipal Council Joginder Nagar have to stop land filling or dumping of mixed waste soon after the timeline for setting up and operationalisation of sanitary landfill is over.

(b) Municipal Council Joginder Nagar have to allow only the non-usable, non-recyclable, non-biodegradable, non-combustible and non-reactive inert waste and pre-processing rejects and residues from waste processing facilities to go to sanitary landfill.

(c) Sites shall meet the specifications as given in Schedule-I of Solid Waste Management Rules, 2016, however, every effort shall be made to recycle or reuse the rejects to achieve the desired objective of zero waste going to landfill.

(d) Municipal Council Joginder Nagar have to investigate and analyse all old open dumpsites and existing operational dumpsites for their potential of biomining and bio-remediation and whereso ever feasible, take necessary actions to bio-mine or bio-remediate the sites.

(e) Municipal Council Joginder Nagar have to ensure that in absence of the potential of bio-mining and bio-remediation of dumpsite, it shall be scientifically capped as per landfill capping norms to prevent further damage to the environment.

CHAPTER—V

MONITORING BY WARD COMMITTEE

Constitution of Ward Sanitation Committee.—A Ward Sanitation Committee shall be constituted in each ward of the Municipal Council Joginder Nagar. The Ward Sanitation Committee shall have 11 to 15 members. The members of the WSC would comprise of ward member, sanitary inspector, tax collector or a designated officer by Municipal Council for each ward, representatives of Residential Welfare Associations (RWAs) of the ward, representatives from slum sanitation committee, representatives of Community Based Organisations (SHGs, youth club etc), local leaders, senior citizens etc. The Ward Sanitation Committee shall oversee the sanitation activity in the ward.

CHAPTER—VI

STAKEHOLDER'S RESPONSIBILITIES

10. Responsibilities of various stakeholders:—

10.1 Responsibilities of Waste Generators:

- (a) No waste generator shall throw the waste generated by him on the street, open spaces, drain or water bodies.

- (b) No person shall let the dirty water, mud, night soil, cow dung, urine, polluted water from their own house, organisation, commercial establishments to accumulate in their own compound nor let it flow on common streets in a way that the environment gets polluted by foul smell or poses a threat to public health.
- (c) To wrap securely used sanitary waste as and when generated in a newspaper or suitable bio-degradable wrapping material and place the same in the domestic bin meant for non-biodegradable waste.
- (d) All citizens shall have the responsibility to dispose of the recyclable waste generated in their complexes to the waste pickers authorised by the Municipal Council or waste collector or containers of the Municipal Council and not put it on the road under any circumstances.
- (e) All waste generators shall pay user fees as specified in these bye-laws.
- (f) No waste generator shall throw, burn or bury the solid waste generated by him on streets, open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies.
- (g) No dead animals or their remains to be thrown in any public places or any such place, which create any kind of pollution.
- (h) If any person is found violating activities prohibited for doing, fine charges shall be collected from the offender by the Municipal Council.

10.2 Responsibility of Ward Sanitation Committee:

- (a) The Ward Sanitation Committee shall oversee the sanitation and cleanliness activities in ward.
- (b) The Ward Sanitation Committee shall act as a grievances redressal point on sanitation issues at ward level.
- (c) The Ward Sanitation Committee shall have the power to impose fine on any offender and also have the power to waive of penalties.
- (d) The Ward Sanitation Committee will promote home composting, bio-gas generation, decentralised processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygiene around the facility.
- (e) The Ward Sanitation Committee will give warning to any offenders of these bye-laws. After two warning by the Ward Sanitation Committee or the Municipal Council / Nagar Panchayat, penalty shall be collected from the violator as per the provisions of these bye-laws.

10.3 Responsibility of the Municipal Council:

- (a) The Municipal Council shall within its territorial area, be responsible for ensuring daily and throughout the year system of cleaning of all common roads, places, temporary settlements, slums, areas, markets, its own parks, gardens, tourist spots, cemeteries and shall be bound to collect the garbage from the nearest declared storage containers, and transport it every day to the final disposal point in closed vehicles for

which the municipal authority may engage private parties on contract or Public Private Partnership mode, apart from its own permanent cleaning staff and vehicles.

- (b) The Municipal Council or the authorized agency engaged by the Municipal Council/ Nagar Panchayat shall provide and maintain suitable community bins on public roads or other public spaces.
- (c) The Municipal Council for the purpose of managing such sanitation activities in decentralised and regular manner shall designate one ward officer, in every ward to supervise the spots of containers, public toilets, community toilets or urinals in public places, transfer station for public garbage, landfill processing units etc. for final disposal of city's garbage.
- (d) The designated ward officer by the Municipal Council shall also be a member of the concerned Ward Sanitation Committee which shall act as the first point of grievance redressal on sanitation issues of the concerned ward and meet complains of citizens on issues of sanitation.
- (e) The Municipal Council shall facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or through any agency for optimum utilisation of various components of solid waste adopting suitable technology including the technologies and the guidelines issued by the Ministry of Urban Development from time to time and standards prescribed by the Central Pollution Control Board.
- (f) The Municipal Council shall create awareness through Information, Education and Communication (IEC) campaign and educate the waste generators on minimal generation of waste, not to litter, re-use the waste to the extent possible, practice segregation of wet bio-degradable waste, dry recyclable and combustible waste and domestic hazardous waste at source, wrap securely used sanitary waste as and when generated in a newspaper or suitable bio-degradable wrapping material and place the same in the domestic bin meant for non-biodegradable waste, storage of segregated waste at source and payment of monthly user fee.
- (g) Chemical fertilizers shall be replaced by use of compost in all parks, gardens maintained by the Municipal Council and any other places within two years of notification.
- (h) Promote recycling initiatives by informal waste recycling sector.
- (i) The Municipal Council shall make efforts to streamline and formalize Solid Waste Management Systems and endeavour that the informal sector workers in waste management (rag pickers) are given priority to upgrade their work conditions and are enumerated and integrated into the formal system of Solid Waste Management in cities.
- (j) Ensure that the operator of a facility provides personal protection equipment including uniform, fluorescent jacket, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling solid waste and the same are used by the workforce.
- (k) Ensure occupational safety of the Municipal Council own staffs and staffs of outsource agency involved in collection, transport and handling waste by providing appropriate and adequate personal protective equipments,

- (I) In case of an accident at any solid waste processing or treatment or disposal facility or landfill site, the officer-in-charge of the facility shall report to the Municipal Council immediately which shall review and issue instructions if any, to the incharge of the facility.

CHAPTER—VII

PROSECUTION & PENALTIES

11. Prosecution:—

- I. Prosecution can be made on violation of above said rules under Municipal Solid Waste Management Rules, 2016, Himachal Pradesh Council Act, 1994 and Environmental Protection Act, 1986. Even the prosecution can be made on the official/workers responsible for implementing so called services under the above said bye-laws if they are not performing their task or delaying their responsibility to implement the services.
- II. Whosoever contravenes the provision of above said bye-laws shall be in addition to the penalties already mentioned under any act/ rules/ laws/bye-laws for time being in force would be liable for disconnection of water supply, electricity and other civic amenities and the Executive Officer of the ULB may request the competent authorities to withdraw any other services if granted in favour of Institution/Commercial Establishment/person committing the offence.

12. Penalties:—

On the violation of above said municipal bye-laws fixed penalties are as below:

Sl. No	Offence	Municipal Council
1.	Littering by People of residential colony	Rs. 500 per day
2.	Open dumping by shopkeepers	Rs. 1000 per day
3.	Littering/ open dumping by restaurants owners	Rs. 2000 per day
4.	Littering/ open dumping by Hotel Owners	Rs. 2000 per day
5.	Littering/ open dumping by Industries	Rs. 5000 per day
6.	Street Vendor like fast-food, chat, ice-cream, juice corner etc.	Rs. 250 per day
7.	Open defecation/ urination in public place	Rs. 500 per offence committed
8.	Disposal of dung in open space / public place	Rs. 2000 per day
9.	Disposal of construction & demolition waste in open space/ road side/ public place by resident	Rs. 2000 per day
10.	Littering of waste like dung, construction & demolition waste on road while transporting through private tractor/ vehicle	Rs. 2000 per day

11.	Disposal of waste water from house in non-authorised place	Rs. 2000 per day
12.	Disposal of sewer in non-authorised place	Rs. 5000 per day
13.	Not keeping of closed dust bins in adequate number & quantity by owners mention from Sl. No 2-6.	Rs. 5000 per day
14.	Spilling of oil, dust, water & other material by road side Motor, Bike, Bicycle repair mechanics.	Rs. 1000 per day
15.	Disposal of skin, feather, blood, flesh or any other material of animal(s) by shopkeeper.	Rs. 2000 per day
16.	Littering by pet animals like dogs, cow, etc. on road side/ open space/ community place.	Rs. 1000 per day
17.	Littering or disposal of waste in front of marriage hall, community place, exhibition hall, mela ground.	Rs. 5000 per day
18.	Encroachment of road for by Dhabas or any other such shop and disposing of waste on road side, open space.	Rs. 1000 per day
19.	Encroachment of road for by fruit, vegetable local vendor and disposing of waste on road side, open space.	Rs. 250 per day
20.	Encroachment of Road hair cutting saloon and disposing of waste on road side, open space.	Rs. 250 per day
21.	Encroachment & disposal of construction & demolition waste in open space/ road side/ public place by businessman, shopkeepers.	Rs. 5000 per day
22.	Disposal of waste by Private Nursing Home/ Hospital, Clinics, Dispensaries on road side, open space.	Rs. 5000 per day
23.	Non-Segregation of waste at source	
i.	Residents	Rs. 250 for first offence and Rs. 500 for second & subsequent offences in a month
ii.	Shopkeepers	Rs. 500 for first offence and Rs. 1000 for second & subsequent offences in a month
iii.	Restaurants owners	Rs.1000 for first offence and Rs. 2000 for second & subsequent offences in a month

iv.	Hotel Owners	Rs.1500 for first offence and Rs. 2500 for second & subsequent offences in a month
v.	Industrial Establishment	Rs. 3000 for first offence and Rs. 5000 for second & subsequent offences in a month
vi.	Sweets, snacks, fast food Lce-creams, sugarcane & other juice and vegetables vendor carts.	Rs. 250 for first offence and Rs. 500 for second & subsequent offences in a month

13. Repeal / Contradict:—

- ✓ Once these byes-laws come into force any other rules, bye-laws, policy with regard to this matter adopted by any ULB will be considered as disaffirm.
- ✓ Any work done or scheme implemented under any previous rules/bye-laws will not be impugn unless until it is just opposite or completely contrary to the action to be taken under the above said bye-laws.

Sd/-
Executive Officer,
Municipal Council,
Joginder Nagar District Mandi Himachal Pradesh.

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 10th January, 2022

No. TPT-F(6)-3/2015-I.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to notify the scheme “Himachal Pradesh Electric Vehicle Policy, 2022” as appended at Annexure – ‘A’, which shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), H.P.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,
Additional Chief Secretary (Transport).

ANNEXURE -‘A’

HIMACHAL PRADESH ELECTRIC VEHICLE POLICY, 2022

1. INTRODUCTION :

Himachal Pradesh (H.P.) is a hilly State located in the North-Western Himalayan ranges. It has forest cover of about 37,033 square km *i.e.*, around 66.52% of the total area of the State. The State annual average Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) concentration is 78.8 micrograms/cubic meter which is higher than the national prescribed limit of 60 micrograms/cubic meter.

To preserve the sensitive mountain ecosystem of H.P. and to address global climate change, H.P. has been an early adopter of clean energy technologies, including renewable energy systems and electric vehicles (EVs). Himachal Road Transport Corporation (HRTC) was the first STU in the country to introduce electric buses. HRTC is operating 75 electric buses in Shimla and on Manali to Rohtang Pass route as well as 50 electric taxis in different cities and towns of the State.

The key reason can be attributed to the vehicular growth of 14.7% which is higher than the national average growth. Similar trends have been observed in growth of personalized vehicles which constitute 85.42% of total vehicle population (18,16,635 on 31-03-2021) whereas their passenger carrying share (38.33%) is less than stage and contract carriages.

Table-1: Source: State Transport Department, Himachal Pradesh (2021)

Total Vehicle Population	Transport		Non-Transport	
18,16,635	2,64,932		15,51,703	
	Category of Vehicle	% share in total population	Category of Vehicle	% share in total population
	Goods (1,72,516)	9.50 %	Two-wheelers (9,48,562)	52.22%
	Contract Carriage (46,197)	2.54%	Cars(5,60,17 6)	30.84%
	Stage Carriage (6504)	0.36 %	Tractors Agri. (12,235)	0.67%
	Public Service Vehicles(1116)	0.06 %	Construction Equipment's (1812)	0.10%
	Tractor/Trailer Commercial (22,047)	1.21 %	Omni/PSV (6,406)	0.35%
	Others(16,552)	0.91%	Others (22,521)	1.24 %
	Total..	14.58%		85.42%

To address the issue of deteriorating air quality of fragile hill ecology, it is important to use cleaner fuels in longer run. Since the State is energy surplus and 90 percent of the power generation is from hydropower, electric mobility has potential to be safe, energy-efficient, eco-friendly and

sustainable mode of transport. It will lead to creation of new jobs and address the issues of adaptation to climate change which had recently shown its visible signs in the form of changing weather pattern, flash floods, water scarcity etc.

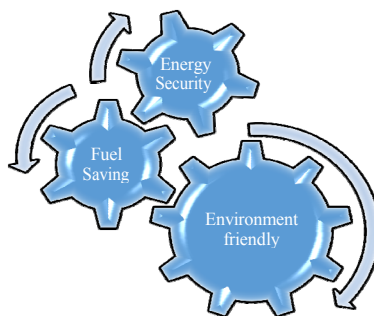


FIGURE 1. NEED FOR EV POLICY:

The State Government is keen to become a leader by decarbonising its transport sector and promoting ecotourism through a combination of renewable energy supply and EV adoption. To boost EV sales, the State has decided to develop the H.P. State EV Policy, 2022.

2. VISION AND MISSION

2.1 VISION:

The State envision to promote clean mobility solutions through faster adoption of EVs. It endeavors to establish Himachal Pradesh as a model State for Electric Vehicle adoption across segments (personal, shared and commercial) and create an ecosystem for manufacturing of Electric Vehicle (EVs) and its components and supporting infrastructure alongwith generating employment in the State.

2.2 MISSION:

1. To save the environment by promoting clean modes of mobility
2. To accelerate demand for EVs and promote manufacturing of EVs in the State
3. To create a conducive environment for the shift from Internal Combustion Engine (ICE) vehicles to EVs.
4. To generate new employment opportunities in the State.

3. OBJECTIVES:

The EV policy objectives shall include:—

- (a) The primary objective of the policy is to accelerate adoption of Battery Electric Vehicles (BEVs) in the State so that they contribute to 15% of new vehicle registrations by 2025.
- (b) To promote sustainable transport system for making Himachal a global hub for electric mobility development and manufacturing of Electric Vehicles (EVs).

- (c) To create public and private charging infrastructure for EV's so that the manufacturers of electric vehicles unit are attracted to set up their manufacturing Unit in the State.
- (d) To provide subsidies and incentives to the electric vehicle manufacturing industries for promoting electric mobility in the State.
- (e) To declare and work towards making Shimla, Mandi, Baddi, Dharamshala as model cities for EV readiness and adoption in the State.

4. STRATEGIES:

The State Government aims to:

- ❖ Promote demand for EVs through the provision of fiscal and non-fiscal incentives
- ❖ Promote dedicated charging infrastructure for charging of EVs through the provision of capital subsidies.
- ❖ Mandate the use of EVs at the institutional level, starting with public transport and government entities.
- ❖ Support the development of EV industrial parks and manufacturing firms through provision of land, infrastructural connectivity, and financial support as per the provision of the H.P. State Industrial Policy, 2019.

5. INCENTIVES

(A) DEMAND CREATION:

INCENTIVES ON PURCHASING AND OPERATING EVs

The State Government will provide demand incentives to accelerate the uptake of EVs. Two types of incentives will be provided—

- (i) incentives on purchase of EVs; and
- (ii) tax/fees waivers.

(I) Purchase incentives.—The purchase incentives will be prescribed by the State Government by notification.

(II) Tax and fee waivers

1. **Commercial permit fees.**—State will waive annual permit fee on commercial EVs in accordance with Ministry of Road Transport and Highways notification S.O.5333 (E).
2. **Road tax.**—State will exempt EVs from road tax (Token) in accordance with Himachal Pradesh Transport Department notification TPT-F (6)-3/2015 for the duration of the policy.
3. **State toll taxes.**—EVs registered in H.P. and other States will be exempted from paying toll taxes on highways for the duration of the policy.

(B) CHARGING INFRASTRUCTURE**(a) Nodal agency:**

Himachal Pradesh State Electricity Board Limited (HPSEBL) has been designated as “State Nodal Agency” for setting up charging infrastructure.

(b) Targets:

1. **Cities.**—At least 1 charging station/point within every 1kmx 1km grid in four model cities-Shimla, Mandi, Baddi and Dharamshala.
2. **Highways.**—At least 1 charging station (on each side) every 25 km on State highways and at least 1 charging point (on each side) every 50 km on busy National Highways in State.

(c) Incentives.—Incentives will be prescribed by the State Government for public and semi-public charging points and/or stations under the policy.**Note:**

* Incentive is limited to the cost of the charging station and does not include the cost of land/ancillary cost to set up a charging station and points.

** Incentive for charging Infrastructure shall be claim from the Production Linked Incentives (PLI) Scheme for National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage of Ministry of Heavy Industries for amounting of Rs. 18100/- Crore.

1. State will define slow/fast/moderate chargers in a notification after the release of the EV policy. Public and semi-public charging stations benefitting from/availing FAME II charging infrastructure incentives will not be eligible for incentives provided under the State EV policy.
2. Definition and details of low-cost AC charging points for light EVs will be provided in a subsequent notification after the policy is released and in accordance with future standards published by the Bureau of Indian Standards (BIS).
3. Private companies will be encouraged to set up charging infrastructure in the State and municipalities can provide them incentives such as land concessions to help set up infrastructure in residential buildings, offices, etc.
4. State Government will consult with and encourage cities to make a share of existing and new public and semi-public parking spaces (e.g. parking spaces in city centres, commercial spaces, housing societies, municipal buildings, railway stations, etc.) EV ready. To support this, the State Government will work towards amending and aligning State building bye-laws with MoHUA’s guidelines/amendments. The amended laws will be applicable for all new buildings and structures.

(d) Local EV readiness plans.—4 model cities will complement State’s EV policy by creating EV readiness plans. The Himachal Transport Department will provide a template for creating the plans after EV policy’s notification.

(e) Tariff structure:

1. HPSEBL will be empowered to set tariff applicable for all EV charging and battery swapping stations across the State.
2. The Board will consider preferential and time-of-use tariffs for EVs
3. The Board will issue a tariff order after this policy's notification

(f) Other strategies to support EV charging infrastructure:

1. State endeavours to set up a single window system to expedite interconnection and installation permissions, details of which will be notified by the nodal agency.
2. Inter-operability through solutions such as open database and flexibility on charger specifications will be encouraged for charging infrastructure supported by the State government.

(C) MANUFACTURING:

1. The State aims to attract investments for EV manufacturing and research and development ecosystem.

2. Incentives for Industries-

- (i) **EV Industrial Parks.**—The Government of Himachal Pradesh will allocate 100 to 200 acres of land as per provisions in the State Industrial Policy of Himachal Pradesh for developing EV parks with adequate infrastructure, common facilities and necessary external infrastructure. These parks will attract manufacturers across the EV ecosystem. A single window clearance mechanism will be created to provide adequate support to companies, especially start-ups, to setup factories and units in the (EV) park.
- (ii) Infrastructure support to manufacturing firms: The Government will provide land, water, electricity and road connectivity as per provisions of the State Industrial Policy, 2019.
- (iii) The State also aims to encourage setting up of vehicle scrapping facilities.

3. Financial Support

The State Government will provide incentives as per H.P. State Industrial Policy, 2019.

(D) OTHER DEMAND CREATION MEASURES:—

1. **Low/zero-emission zones.**—The four model cities (*i.e.* Shimla, Mandi, Baddi and Dharamshala) will be required to create at least 1 low/zero-emission zone where only EVs, walking and cycling are permitted. State Government will priorities tourist spots; eco-sensitive areas, and reserve forests for creation of low emission zones.

2. State Government will explore the possibility of aggregating e-buses as per Department of Heavy Industry's Policy.
3. State Government will create a plan for switching existing Government fleet and public transport to EVs in phases.

6. FUNDING MECHANISM:

1. **State EV fund.**—The State will use 95% funds of the Green Tax and compounding fee under Motor Vehicle Act/Rules collected by the Transport Department during the policy period.
2. **Charging Infrastructure.**—State Government will create charging infrastructure on the Production Linked Incentives (PLI) Scheme for National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage of Ministry of Heavy Industries.
3. State will dovetail funds under Smart City Projects, BBNDAs and Municipal bodies for creation of EV Infrastructure for promotion of EV infrastructure in four model towns *i.e.* Dharamshala, Shimla, Mandi & Baddi respectively.

7. GOVERNANCE:

1. **Implementation Body.**—State will create an EV Board / Cell /Council or Secretariat to ensure effective implementation. This body will monitor policy progress and develop operational guidelines for an efficient mechanism for transfer of incentives for EVs and EV charging points to buyers.
2. **Ongoing stakeholder consultations.**—Following policy's notification, the State will hold regular consultations with industry, energy operators, banks and other financial institutions, civil society organisations, etc. to ensure smooth implementation of the policy and its provisions.
3. **Awareness campaign.**—State Government will aim to launch an awareness campaign to promote EVs. The campaign will target to reach to all key EV stakeholders in the State, including EV dealerships, OEMs, consumers, and financial institutions. The campaign will aim to create awareness about EVs in terms of their benefits, incentives provided by the State and Central policies, need to adopt green transport and more. Schools and Colleges will be encouraged to educate students about clean mobility solutions.

8. POLICY VALIDITY :

The policy will be valid for five years from the date of issue of relevant government resolution.

ANNEXURES

DEFINITIONS

Electric Vehicle (EV).—As per Government of India Notification dated 16-09-2005 under Central Motor Vehicle Rule 1989 Rule No. 2(u) "Battery Operated Vehicles" means a vehicle

adapted for use upon roads and powered exclusively by an electric motor whose traction energy is supplied exclusively by traction battery installed in the vehicle. Except e-Rickshaw/e-Cart all EVs shall be equipped with "electric regenerative braking system" which provides for the conversion of kinetic energy into electrical energy during braking.

EV Components.—Major components of EV include motor controller, electric engine (motor), regenerative braking, drive system and related parts/assemblies.

EV Battery.—An electric vehicle Battery (EVB) or traction battery used to power the propulsion of battery electric vehicles (BEVs). Vehicle batteries are usually a secondary (rechargeable) battery. EV battery will not include Lead-acid batteries.

EV Battery Components.—Battery pack designs for EVs incorporate a combination of several mechanical and electrical component systems which perform the basic required functions of the pack. Battery pack consists of many discrete cells connected in series and parallel to achieve the total voltage and current requirements of the pack. A battery comprises of similar stacks called modules, which are placed into a single pack. Modules also incorporate cooling mechanisms, temperature monitors, other devices and Battery Management System (BMS).

EV Charging Station Equipment.—An electric vehicle fast charging station (charging time under 1 hour) also called EV charging station, electric recharging point, charging point, charge point and EVSE (electric vehicle supply equipment), is an element in an infrastructure that supplies electric energy for the recharging of electric vehicles. The charging station equipment consists of charging posts, charging cabinets, fully automated charging stations integrated with power distribution equipment etc.

EV Charging Infrastructure.—The policy envisages three type of charging facilities, viz. Domestic user facility (individual) Public charging facility (government facilities, railway stations etc.) Commercial charging facility (roadside, malls, parking stations, fuel stations etc.).

Light Electrical Vehicles.—Electric Vehicles with battery packs of below 120V is considered as Light Electric Vehicle and they shall include two wheelers, three wheelers and some car models also.

Two Wheelers.—E-Scooter with a built in 50 Km range battery (suitable for charging at home) with provision for additional 50Km range extension battery (swappable at public stations as per requirement).

E-scooters with two swappable batteries.

Three Wheelers.—Auto rickshaws in the State having a base price of Rs. 1 lakh to 1.70 lakh with a running cost in the range Rs. 1.30 to Rs. 1.40 per km and converting these as e-autos can be made revenue neutral, if the Electric Vehicle (EV) battery is addressed as a separate component from the base Electric Vehicle (EV).

Four Wheelers.—Electric carts can be used for government use and as a modern, eco-friendly taxi car. Technologically, the optimal solution would be to have the electric carts with built-in batteries with hireable range extension batteries of different capacities to different models of Electric Vehicle (EV).

Built-in batteries could be charged at home over night and could run for about 80-100 KM distance daily which would be the normal demand of the car owners whereas the range extension batteries could be hired for longer drives.

There could also be a number of Direct Current (DC) fast charging stations as well as swapping stations for range extension batteries established in strategic locations in the cities and along the national highways and State highways. It would also be possible to provide the public the list and geographic location of all available swapping stations over as mobile app accessible to all.

Heavy Electrical Vehicles/Electric Buses.—Electric vehicles with a battery pack of more than 500 Volt.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th January, 2022

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Palampur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC, Jaisinghpur, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the paternity leave period of Sh. Ajay Kumar, Civil Judge-cum-JMFC, Jaisinghpur, H.P. *w.e.f.* 31-12-2021 to 14-01-2022 or till he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th January, 2022

No. HHC/GAZ/14-391/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 07 days earned leave *w.e.f.* 04-12-2021 to 10-12-2021 in favour of Ms. Eeshani Sharma, Civil Judge-cum-JMFC (II), Sundernagar, H.P.

Certified that Ms. Eeshani Sharma had joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Eeshani Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC (II), Sundernagar, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 1st January, 2021*

No. HHC/GAZ/14-393/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 05 days earned leave *w.e.f.* 20-12-2021 to 24-12-2021 with permission to prefix Sunday falling on 19-12-2021 and suffix Gazetted holiday & Sunday falling on 25-12-2021 & 26-12-2021, already sanctioned *vide* this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-393/2019-31609-17, dated 18-12-2021 in favour of Sh. Yudh Veer Singh, Civil Judge-*cum*-JMFC, Karsog, H.P.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 4th January, 2022*

No. HHC/GAZ/14-367/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 156 days maternity leave *w.e.f.* 06-07-2021 to 08-12-2021 in favour of Ms. Deepika Negi, the then Civil Judge-*cum*-JMFC (II), Dharamshala presently posted as Civil Judge-*cum*-JMFC, Baijnath, District Kangra, H.P.

Certified that Ms. Deepika Negi has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Deepika Negi would have continued to hold the same post of Civil Judge-*cum*-JMFC (II), Dharamshala, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 4th January, 2022*

No. HHC/GAZ/14-410/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 02 days commuted leave for 13-12-2021 and 14-12-2021 in favour of Ms. Priyanka Devi, Civil Judge-*cum*-JMFC (III), Amb, H.P.

Certified that Ms. Priyanka Devi had joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Priyanka Devi would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC (III), Amb, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th January, 2022

No. HHC/GAZ/14-371/2016.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 02 days commuted leave for 09-12-2021 and 10-12-2021 in favour of Sh. Tarun Walia, Civil Judge-cum-JMFC (III), Una, H.P.

Certified that Sh. Tarun Walia had joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Tarun Walia would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC (III), Una, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th January, 2022

No. HHC/Admn.16 (34)89-III.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Naveen Singh (HIM/131/2017) Advocate, as Oath Commissioner at Chamba, H.P. for a period of two years with effect from 07-01-2022, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, 11th January, 2022*

No. Pub-B(9)-1/2018.—In pursuance to the instructions of the Department of Personnel issued *vide* letter No. Per(AP)C-B(2)-1/2019 dated 28th December, 2021 and on the recommendations of the Departmental Screening Committee constituted for the purpose, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the regularisation of the following District Public Relations Officer/Information Officer in Information and Public Relations Department in the pay band of ₹ 10300—34800 + ₹ 5400 Grade Pay, after completion of two years service on contract basis as on 30-09-2021:

Sl. No.	Name and designation of the Officers	Present place of posting
1.	Sh. Devender Kumar, IO	Directorate
2.	Sh. Simpal Saklani, DPRO	Sirmaur at Nahan

II. The above mentioned officers are regularised subject to the following terms and conditions:—

1. The Officers will be on probation for a period of two years.
2. The contractual appointees will be eligible for regularisation against available vacancies.
3. The regularisation will be strictly on the basis of seniority subject to condition that eligibility criteria etc., prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post have been observed at the time of their initial recruitment on contract basis. The seniority of above DPROs/IOs shall remain intact as per the initial contract irrespective of their joining. The name of aforesaid officers will be kept below *i.e.* immediate after last DPRO/IO presently working in the Department on regular basis in the seniority list of the DPRO/IO and will not confer any right to them for claiming seniority above the regular DPRO/IO already working in the Department.
4. The candidate should be medically fit for the post against which he/she is being considered for regularisation. Obtaining the Medical fitness certificate of the candidate (from the concerned CMO which will further be furnished to the Director, I&PR through concerned Controlling Officer) shall be ensured in accordance with the provisions contained in FR 10 and SR 4(1), 4(2) and 4(3).
5. The regularisation shall be subject to verification of character and antecedents of the candidate being considered for regularisation as provided in the H.P. Financial Rules, 2009.

6. For determination of the date of birth of the candidate concerned, the criteria as laid down in Rule 172 of the Himachal Pradesh Financial Rules, 2009 shall be observed.
 7. The contractual appointee who is to be regularised shall be appointed at the minimum of the time scale of the post.
 8. The contractual appointee who is to be regularised shall be liable to be posted anywhere in the State.
 9. The regularisation will be with prospective effect *i.e.* from the date of issue of regularisation orders.
 10. Observance of reservation in the service as per instructions of the State Government from time to time have already been done at the time of initial appointment on contract basis.
 11. The regularisation will be governed by Service Rules and orders etc. in force from time to time as applicable in H.P. Government and Central Rules such as CCA Rules, 1961 and Conduct Rules, 1964 as are applicable in Himachal Pradesh.
 12. The appointment is provisional and subject to the educational qualification and other certificates being verified by the Director, Information and Public Relations, H.P.
 13. The regularised officer will have to give a declaration to the effect that he has only one living spouse, if married.
 14. He will have to take an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India or making a solemn affirmation.
 15. He will have to produce all the certificates in original at the time of joining in the Directorate of Information and Public Relations.
 16. The regularised officer will submit a statement of his movable and immovable properties as per the proforma prescribed in the CCS (Conduct Rules) 1964, within a period of 30 days.
- III. If above terms and conditions are acceptable to him/her, he/she is directed to report for duty to the concerned controlling officer within a period of two weeks from issuance of this notification failing which his regularisation order shall stand cancelled and no further extension shall be granted.
- IV. Above Officers are directed to continue to work at same station. However, they are required to join duty on regularisation and send their joining report to this department through proper channel.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,
Additional Chief Secretary (I&PR).

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT**OFFICE ORDER***Shimla-2, the 11th January, 2022*

No. Pub-B(9)-1/2022.—In pursuance to the instructions of the Department of Personnel issued *vide* letter No. Per(AP)C-B(2)-1/2019 dated 28th December, 2021 and on the recommendations of the Departmental Screening Committee constituted for the purpose, the following Assistant Public Relations Officers are hereby regularised in Information and Public Relations Department in the pay band of ₹10300—34800 + ₹ 4200 Grade Pay, after completion of two years service on contract basis as on 30-09-2021:—

Sl. No.	Name of the Assistant Public Relations Officers	Present place of posting
1.	Sh. Jai Prakash	Keylong
2.	Sh. Tarjeev Kumar	Ani
3.	Sh. Chandan Anand	Dehra
4.	Ms. Upma Thakur	Directorate
5.	Sh. Hemant Kumar	Nahan
6.	Sh. Nitish Kumar	Rohru
7.	Sh. Sanjay Kumar	Directorate

II. The above mentioned officials are regularised subject to the following terms and conditions:—

1. The Officials will be on probation for a period of two years.
2. The contractual appointees will be eligible for regularisation against available vacancies.
3. The regularisation will be strictly on the basis of seniority subject to condition that eligibility criteria etc., prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post have been observed at the time of their initial recruitment on contract basis. The seniority of above APROs shall remain intact as per the initial contract irrespective of their joining. The name of aforesaid officers will be kept below *i.e.* immediate after last APRO presently working in the Department on regular basis in the seniority list of the APROs and will not confer any right to them for claiming seniority above the regular APROs already working in the Department.
4. The candidate should be medically fit for the post against which he/she is being considered for regularisation. Obtaining the Medical fitness certificate of the candidate (from the concerned CMO which will further be furnished to the Director, I&PR through concerned Controlling Officer) shall be ensured in accordance with the provisions contained in FR 10 and SR 4(1), 4(2) and 4(3).

5. The regularisation shall be subject to verification of character and antecedents of the candidate being considered for regularisation as provided in the H.P. Financial Rules, 2009.
 6. For determination of the date of birth of the candidate concerned, the criteria as laid down in Rule 172 of the Himachal Pradesh Financial Rules, 2009 shall be observed.
 7. The contractual appointee who is to be regularised shall be appointed at the minimum of the time scale of the post.
 8. The contractual appointee who is to be regularised shall be liable to be posted anywhere in the State.
 9. The regularisation will be with prospective effect *i.e.* from the date of issue of regularisation orders.
 10. Observance of reservation in the service as per instructions of the State Government from time to time have already been done at the time of initial appointment on contract basis.
 11. The regularisation will be governed by Service Rules and orders etc. in force from time to time as applicable in H.P. Government and Central Rules such as CCA Rules, 1961 and Conduct Rules, 1964 as are applicable in Himachal Pradesh.
 12. The appointment is provisional and subject to the educational qualification and other certificates being verified by the Director, Information and Public Relations, H.P.
 13. The regularised official will have to give a declaration to the effect that he has only one living spouse, if married.
 14. He will have to take an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India or making a solemn affirmation.
 15. He will have to produce all the certificates in original at the time of joining in the Directorate of Information and Public Relations.
 16. The regularised official will submit a statement of his movable and immovable properties as per the proforma prescribed in the CCS (Conduct Rules) 1964, within a period of 30 days.
- III. If above terms and conditions are acceptable to him/her, he/she is directed to report for duty to the concerned controlling officer within a period of two weeks from issuance of this notification failing which his regularisation order shall stand cancelled and no further extension shall be granted.
- IV. Above officials are directed to continue to work at same station. However, they are required to join duty on regularisation and send their joining report to this department through proper channel.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,
Additional Chief Secretary (I&PR).

SPECIFIC NOTIFICATION**FINANCE DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla, the 20th January, 2022*

No. Fin-2-C(12)-3/2021 (I).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of **12-year** tenure for an aggregate amount of **Rs. 500 crore** (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan

1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.
- (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the **yield** based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. The Government Stock up to 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on **January 24, 2022**. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on **January 24, 2022**.
 - (a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.
 - (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on **January 25, 2022**.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on **January 25, 2022** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/ New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort) /New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of **12-year** tenure. The tenure of the Stock will commence on **January 25, 2022**.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on **January 25, 2034**.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on **July 25 and January 25**.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

*Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh
Finance Department.*

SPECIFIC NOTIFICATION**FINANCE DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Shimla, the 20th January, 2022

No. Fin-2-C(12)-3/2021(II).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of **15-year** tenure for an aggregate amount of

Rs. 500 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-II/2003, dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan

1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.
- (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai- 400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-II/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the **yield** based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. The Government Stock up to 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure - II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400 001 on **January 24, 2022**. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on **January 24, 2022**.
 - (a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.
 - (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on **January 25, 2022**.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on **January 25, 2022** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/ New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort) /New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of **15-year** tenure. The tenure of the Stock will commence on **January 25, 2022.**

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on **January 25, 2037.**

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on **July 25 and January 25.**

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

*Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh
Finance Department.*

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री जैल सिंह पुत्र श्री सुफल सिंह, गांव अखल, डा0 खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री जैल सिंह पुत्र श्री सुफल सिंह, गांव अखल, डा0 खुन्देल, उप-तहसील धरवाला ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरे पिता का नाम सुफल सिंह है जो सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल बलोठ में सुफल पुत्र तानी गलत दर्ज है जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र, हि0 प्र0 द्वारा सूचित किया जाता है कि सुफल सिंह पुत्र तानी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 22-01-2022 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री गिजो राम पुत्र निहाला, गांव भजलूई, डा0 बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्राथी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्राथी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि मेरा नाम महाल दरभेटा के राजस्व रिकार्ड में गिजो गलत दर्ज है। लेकिन अन्य दस्तावेजों परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड व शिक्षा प्रमाण-पत्र में मेरा नाम गिजो राम सही दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्राथी ने महाल दरभेटा की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्राथी के ही हैं तथा उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्राथी ने चाहा है कि मेरा नाम राजस्व रिकार्ड महाल दरभेटा में गिजो के बजाए गिजो राम दुरुस्त दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्राथी गिजो राम पुत्र निहाला के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 22-01-2022 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्रीमती कमला शर्मा पत्नी शाम डोगरा, निवासी Near Employment Exchange, गांव व डा0 अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

Subject :—permission for delayed birth registration.

इस कार्यालय में श्रीमती कमला शर्मा, पत्नी शाम डोगरा, निवासी New Employment Exchange, गांव व डा0 अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरी लड़की का नाम बिन्दू शर्मा का जन्म दिनांक 26-08-1986 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुन्देल के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत खुन्देल को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त बिन्दू शर्मा पुत्री शाम डोगरा व श्रीमती कमला शर्मा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुन्देल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-01-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुन्देल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील धरवाला,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री देसो पुत्र श्री रिझू, गांव पनेठ, डा0 चूडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

... प्रत्यार्थीगण।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री देसो पुत्र श्री रिझू, गांव पनेठ, डा0 चूडी, उप-तहसील धरवाला ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा नाम देसो पुत्र रिझू है जो सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल चूडी में देस राज पुत्र रिझू गलत दर्ज है जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र, हि0 प्र0 द्वारा सूचित किया जाता है कि देसो पुत्र श्री रिझू के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-02-2022 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री जै सिंह, गांव हिण्ड, डा0 पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री जै सिंह, गांव हिण्ड, डा0 पियुहरा, उप-तहसील धरवाला ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा नाम महेन्द्र कुमार है जो सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल पियुहरा में भिन्दर कुमार गलत दर्ज है जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र, हि0 प्र0 द्वारा सूचित किया जाता है कि महेन्द्र कुमार पुत्र श्री जै सिंह के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-01-2022 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 34 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2021

तारीख दायरा : 20-11-2021

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव नौण, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव नौण, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरी माता का नाम परिवार रजिस्टर

नकल, मृत्यु प्रमाण-पत्र में श्रीमती मीनो देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल व पटवार वृत्त राजनगर, उप-तहसील पुखरी में मेरी माता का नाम मीना पत्नी ज्ञानू दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की माता के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किसम का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी की माता का नाम मीना के बजाए मीनो देवी पत्नी श्री ज्ञानू दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त राजनगर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-01-2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Raman Kumar aged 45 years s/o Sh. Bali Ram, r/o Village Ajal, P.O. Chamiana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Santosh Thakur aged 42 years d/o Sh. Ajit Singh, Village Lahalri, P.O. Dugha, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

Applicants.

Versus

The General Public

Respondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Raman Kumar aged 45 years s/o Sh. Bali Ram, r/o Village Ajal, P.O. Chamiana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Santosh Thakur aged 42 years d/o Sh. Ajit Singh, Village Lahalri, P.O. Dugha, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 16-01-2004 at Village Ajal, P.O. Chamiana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-01-2022. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 23-12-2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Shiv Mahajan aged 34 years s/o Sh. Ajay Gupta, r/o Village Ward No.9, Jain Mohalla Sujanpur, P.O. Sujanpur, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Shruti Khanna aged 35 years d/o Brij Lal Khanna c/o Ranjeet Parkash Seth at Maitri Apartment, Plot No. 5, Mayur Vihar, Phase-1, Patparganj, East Delhi-110091 *Applicants.*

Versus

The General Public

Relpondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Shiv Mahajan aged 34 years s/o Sh. Ajay Gupta, r/o Village Ward No.9, Jain Mohalla Sujanpur, P.O. Sujanpur, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Shruti Khanna aged 35 years d/o Brij Lal Khanna c/o Ranjeet Parkash Seth at Maitri Apartment, Plot No. 5, Mayur Vihar, Phase-1, Patparganj, East Delhi-110091 have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 20-04-2014 at S.M. Convention Hall Palampur, District Kangra (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-02-2022. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 05-01-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Parveen Kumar aged 23 years s/o Sh. Satish Kumar, r/o V.P.O. Ree, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Pushpa aged 19 years d/o Surender Bahadur, r/o V.P.O. & Tehsil Maikuna, District Surkhet, State Kathmandu, Nepal at present c/o Urimila Devi d/o Late Sh. Roshan Lal Village Amaroh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

The General Public

. . *Respondent.*

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Parveen Kumar aged 23 years s/o Sh. Satish Kumar, r/o V.P.O. Ree, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Pushpa aged 19 years d/o Surender Bahadur, r/o V.P.O. & Tehsil Maikuna, District Surkhet, State Kathmandu, Nepal at present c/o Urimila Devi d/o Late Sh. Roshan Lal, Village Amaroh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) through Counsel Sh. Himanshu Sharma have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-02-2022. The objections received after 15-02-2022 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 05-01-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

(Dr. Harish Gajju) H.A.S.,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Sunil Kumar aged 25 years s/o Sh. Shali Gram, r/o Village Chhaner, P.O. Chamiana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Priya Kumari aged 18 years d/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village Awah, P.O. Salouni, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

The General Public

.. Respondent.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Sunil Kumar aged 25 years s/o Sh. Shali Gram, r/o Village Chhaner, P.O. Chamiana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Priya Kumari aged 18 years d/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village Awah, P.O. Salouni, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) through Counsel Sh. Punit Kumar have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-02-2022. The objections received after 15-02-2022 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 05-01-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

(Dr. Harish Gajju) H.A.S.,

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Additional District Registrar of Marriage-cum- Sub-Divisional Magistrate,
Sub-Division Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Akash Guleria s/o Sh. Vijay Guleria, r/o Village Ghanal Kalan, Ward No. 7, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Shreya Devi d/o Sh. Manoj Kumar, r/o Village Bhadiyata, P.O. Dalhousie Cantt., Tehsil & District Chamba (H.P.) .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Registration of marriage under section 8 (3) of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996

WHEREAS, an application under section 8 (3) of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996 has been received from Sh. Akash Guleria and Smt. Shreya Devi alongwith documents and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 03-08-2021 at Village Bhadiyata, P.O. Dalhousie Cantt., Tehsil & District Chamba (H.P.) and same could not be registered, under the act *ibid* in the office of the Local Registrar Marriage-cum-Secretary, Gram Panchayat Anu, Tehsil and District Hamirpur, H.P. within stipulated period due to unavoidable circumstances.

NOW, THEREFORE, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding registration of this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 07-02-2022. In case no objection is received by 07-02-2022, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 29-12-2021.

Seal.

Sd/-

*Additional District Registrar of Marriages-
cum- Sub-Divisional Magistrate,
Sub-Division, Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Parma Nand, r/o House No. 271, Ward No. 01, Krishna Nagar, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Reeta Devi d/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Sandhwan, P.O. Sudhial, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage.

Sh. Sunil Kumar and Ms. Reeta Devi have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months. The notice has been issued to the General Public on dated 18-09-2021, but applicants could not make their presence before this court within three months. The applicants again filed an application before this court and further stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 05-02-2022. In case no objection is received by 05-02-2022, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 31-12-2021.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Dr. Charanji Lal, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Dilwar Kumar s/o Sh. Jagar Nath, r/o Village Jablana, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) presently residing at c/o Sh. Ashwani Kumar s/o Sh. Roshan Lal, r/o House No. 141, Ward No. 10, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Sunaina Thakur d/o Sh. Virender Singh, r/o Village Dharat, P.O. Majhwar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage.

Sh. Dilwar Kumar and Ms. Sunaina Thakur have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 08-02-2022. In case no objection is received by 08-02-2022, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 29-12-2021.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Dr. Charanji Lal, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Rahul Kumar s/o Sh. Ravi Kumar, r/o Village & P.O. Harsi, Ward No. 2, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.) presently residing at c/o Sh. Goldi s/o Sh. Joginder Singh, r/o Village Kala Amb (Bharin), P.O. Ropa, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Shikha d/o Sh. Ranjinder Kumar, r/o Village Soul Banehr, P.O. Upper Lambagaon, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage.

Sh. Rahul Kumar and Ms. Shikha have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 08-02-2022. In case no objection is received by 08-02-2022, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 29-12-2021.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)

रोशन लाल पुत्र श्री नानकू राम, निवासी वही, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

रोशन लाल पुत्र श्री नानकू राम, निवासी वही, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके दादा केसरू राम की मृत्यु दिनांक 12-01-1990 को महाल वही में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-01-2022 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में अदालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 05-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)**

श्री सुमीत कुमार, निवासी सवडी, डा0 सवडी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुमीत कुमार, निवासी सवडी, डा0 सवडी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी सुमन कुमार की मृत्यु दिनांक 02-06-2018 को महाल सवडी में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-01-2022 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असातन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 05-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 3133/NT/21

Sh. Bansi Lal s/o Late Sh. Jagat Ram, r/o Uparli Barol, V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Bansi Lal s/o Late Sh. Jagat Ram, r/o Uparli Barol, V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी बेटी का जन्म दिनांक 13-06-1984 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे

पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Richa d/o Bansil Lal के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-01-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 13-06-1984 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 3132/NT/21

Sh. Hari Dass s/o Sham Sunder, r/o Ward No. 1, Dharamkot, V.P.O. Bhagsunag Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Hari Dass s/o Sham Sunder, r/o Ward No. 1, Dharamkot, V.P.O. Bhagsunag Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी बेटी का जन्म दिनांक 10-07-2004 को हुआ है परन्तु एम० सी० धर्मशाला/ ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Viola Dass d/o Hari Dass के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-01-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 10-07-2004 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 27-01-2022

श्रीमती सोमा देवी पत्नी श्री अमरनाथ, निवासी गांव व डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल रजोल में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति का सही नाम अमरनाथ पुत्र श्री किरहू है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल रजोल में जगरनाथ पुत्र श्री किरहू दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके जगरनाथ उर्फ अमरनाथ पुत्र श्री किरहू करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 27-01-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 24-01-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 11/C/2021

तारीख दायरा : 29-12-2021

तारीख पेशी : 28-01-2022

सुरिंद्र कुमार पुत्र जय लाल, वासी महाल स्वाणा उपरला, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा उपरला में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा उपरला में शिंदल सिंह पुत्र जय लाल पुत्र मुन्शी दर्ज है

जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत स्वाणा में सुरिंद्र कुमार पुत्र जय लाल दर्ज है। जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा उपरला में शिंदल सिंह उपनाम सुरिंद्र कुमार पुत्र जय लाल पुत्र मुन्शी के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2022 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-12-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री राजेन्द्र पाल व अजय कुमार पुत्रान व सदेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री रामेश्वर दत्त व महिन्दर पाल व जय सिंह पुत्रान रुलिया राम, गांव व डाकघर डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

1. राज किशोर, 2. दीप सिंह पुत्रान रघुवीर सिंह, 3. विपन कुमार पुत्र, 4. बनीता कुमारी पुत्री शशी कला, 5. विजय कुमारी, 6. रेखा कुमारी पुत्रियां रघुवीर सिंह, 7. नरेश कौर विधवा, 8. अनु कुमारी व 9. रेणु कुमारी हाल पत्नी संजीव कुमार, 10. मनु कुमारी पुत्रियां रंजीत सिंह, 11. कुशल कुमार, 12. जीवन कुमार, 13. कुलदीप कुमार पुत्रान व 14. सुषमा कुमारी पुत्री राम प्यारी हाल पत्नी विनोद कुमार, 15. परमजीत पत्नी, 16. संजीव कुमार, 17. विवेक कुमार पुत्रान व 18. संयोगिता पुत्री सुरिन्दर कुमार हाल पत्नी आँचल सिंह, 19. लीला देवी पत्नी, 20. लबली, 21. पवन कुमार, 22. मुनीष कुमार पुत्रान सुदर्शन कुमार, 23. रछपाल, 24. सतीश, 25. दिनेश कुमार, 26. रमेश पुत्रान व 27. तृप्ता देवी, 28. सोन देवी पुत्रियां चूहडू हाल पत्नी सुरजीत सिंह, 29. राज कुमारी विधवा, 30. मुनीष कुमार, 31. राजेश कुमार पुत्रान सेवक, 32. नरेश कुमार, 33. राज कुमार पुत्र प्रेमा के वारसान:-नीलम कुमारी पत्नी, आरती, भारती, शिखा पुत्रियां राजकुमार, 34. सोनिया कुमारी पुत्री विहारी लाल। प्रत्यार्थीगण।

उनवान मुकद्दमा.—तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0, भू-राजस्व अधिनियम 1954, बाबत भूमि खाता नं0 144, खतौनी नं0 197 ता 205, खसरा कित्ता 33, रकबा तादादी 0-95-61 है0 वाक्या महाल डाडासीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा श्री राजेन्द्र पाल व अजय कुमार पुत्रान व सदेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री रामेश्वर दत्त व महिन्दर पाल व जय पाल पुत्रान रुलिया राम, निवासी महाल तहसील व डाकघर डाडा सीबा ने इस तहसील के अन्तर्गत दायर किया है। वादी को उपरोक्त प्रतिवादीगणों का सही पता मालूम न है। वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र पर लिखे गए पता अनुसार उपरोक्त प्रतिवादीगणों को बजरिया समन/रजिस्टर समन द्वारा सूचित किया गया परन्तु प्रतिवादी बार-बार समन करने के बावजूद भी हाजिर न हो रहे हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगणों को बजरीया राजपत्र इशतहार सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि की तकसीम बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2022 को सांय 5.00 बजे असागतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो समझा जावेगा कि उक्त भूमि की तकसीम करने

बारे किसी को कोई आपत्ति न है तथा मामले में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर मामले का निपटारा किया जाएगा।

आज दिनांक 28-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नाम दुरुस्ती नम्बर : 15

तारीख दायर : 27-12-2021

तारीख पेशी : 27-01-2022

श्री सुरेन्द्र पौल शर्मा पुत्र स्व0 श्री रेवत राम शर्मा, निवासी गांव खुड्डी, डाकघर व तहसील सन्धोल,
जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।

श्री सुरेन्द्र पौल शर्मा पुत्र स्व0 श्री रेवत राम शर्मा, निवासी गांव खुड्डी, डाकघर व तहसील सन्धोल,
जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम सुरेन्द्र पौल
शर्मा है जबकि राजस्व अभिलेख महाल सन्धोल में उसका नाम सुरेन्द्र कुमार दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये
प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल सन्धोल में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम सुरेन्द्र कुमार
उर्फ सुरेन्द्र पौल शर्मा दर्ज किया जाये।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी
आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि
किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 27-01-2022 को
प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर
हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार
निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)**

मिसल जन्म पंजीकरण नं0 : 14 तारीख दायर : 27-12-2021

तारीख पेशी : 27-01-2022

श्री तिलक राज शर्मा पुत्र श्री हरि राम शर्मा, निवासी गांव लसराणा, डाकघर व तहसील सन्धोल,
जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

श्री तिलक राज शर्मा पुत्र श्री हरि राम शर्मा, निवासी गांव लसराणा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने के उपरान्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी से उनके कार्यालय के पत्र संख्या: HFW-MND (Delayed Birth & Death) 2021/-20430, दिनांक 09-11-2021 द्वारा श्री तिलक राज शर्मा पुत्र श्री हरि राम शर्मा का विलम्बित जन्म पंजीकरण मामला समस्त औपचारिकताओं सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा श्री तिलक राज शर्मा पुत्र श्री हरि राम शर्मा की जन्म तिथि 07-07-1957 को होने की पुष्टि करते हुए जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व नियम 9 (3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, 2003 के तहत अनुमति प्रदान करते हुए निर्देश दिए हैं कि मामला में उक्त अधिनियम में निहित शर्तों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही सम्बंधित ईकाइ (ग्राम पंचायत दतवाड़) को परिवार रजिस्टर व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम एवं जन्म तिथि की प्रविष्टि करने हेतु भेजा जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 27-01-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**In the Court of Sh. Paras Aggarwal (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Megh Singh s/o Lesru Ram, r/o Village Luhari, P.O. Thachi, Tehsil Bali Chowki, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Neelam Kumari d/o Sh. Dina Nath, r/o Village Luhari, P.O. Thachi, Tehsil Bali Chowki, District Mandi (H.P.)
.. Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Megh Singh and Smt. Neelam Kumari have filed an application on 29-12-2021 along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 09-04-2021 and they are living as husband and wife since then and hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-01-2022. The objection received after 28-01-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 29-12-2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Shri B. R. Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Sh. Yashpal Kumar s/o Sh. Nand Lal, r/o Village Patshal Kalan, P.O. Kalihatti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Yashpal Kumar s/o Sh. Nand Lal, r/o Village Patshal Kalan, P.O. Kalihatti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his own named— Sh. Yashpal Kumar s/o Sh. Nand Lal, r/o Village Patshal Kalan, P.O. Kalihatti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy.-cum-Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Maily (Jejad), Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Sh. Yashpal Kumar	Own	04-05-1988

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of Birth of above named in the record of Secy.-cum-Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Maily (Jejad), Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh, may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 17-01-2022 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Shri Surender Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H. P.)

Smt. Neeta Dutta w/o Sh. Naresh Kumar Datta, r/o Village Kalgaon, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh ..Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Neeta Dutta w/o Sh. Naresh Kumar Datta, r/o Village Kalgaon, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her son named— Mr. Eklavya Dutta , r/o Village Kalgaon, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy.-cum-Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Katlaha, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Mr. Eklavya Dutta	Son	09-03-2007

Therefore, you are in formed through this notice that any person who has any objection regarding registration of above mentained name can file the objection personally or in written before this court on or before 17-02-2022. The objections received after 17-02-2022 will not be intertained an necessary orders will be passed.

Issued today on 17-01-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kamay D'Souza s/o Sh. Mohan Lal, r/o Thana-Dhar, Bhuiara, Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) declares that earlier I have changed my name from Kamlender Kumar to Kamay D'Souza & now I again want to change my name from Kamay D'Souza to Kartik Dhawan. Please note.

KAMAY D'SOUZA,
s/o Sh. Mohan Lal,
r/o Thana-Dhar, Bhuiara,
Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Suresh Bakshi s/o Late Sh. Chunni Lal Bakshi, r/o Narwana Bazar, Yol, Tehsil Dharmashala, District Kangra (H.P.) declares that Suresh Bakshi & Suresh Vaid is the name of one & same person. All note.

SURESH BAKSHI,
s/o Late Sh. Chunni Lal Bakshi,
r/o Narwana Bazar, Yol,
Tehsil Dharmshala, District Kangra (H.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, सुशील कुमार N.K. 14936193, Mech- Infantry, 56 APO, निवासी वी.पी.ओ. चौआर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) घोषणा करता हूं कि मेरे आर्मी रिकार्ड में मेरी पत्नी सुमन कुमारी का नाम गलती से पूजा ठाकुर उर्फ पूजा जसवाल दर्ज है जिसे सही कर सुमन कुमारी दर्ज किया जाए।

सुशील कुमार,
N.K. 14936193, Mech- Infantry, 56 APO,
निवासी वी.पी.ओ. चौआर, तहसील अम्ब,
जिला ऊना (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Geeta Devi Chauhan w/o Sh. Ajay Kumar Chauhan, r/o Army Public School Dagshai, Tehsil and District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Geeta Chauhan to Geeta Devi Chauhan. Please note.

GEETA DEVI CHAUHAN
w/o Sh. Ajay Kumar Chauhan,
r/o Army Public School Dagshai,
Tehsil and District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sh. Ajay Kumar Chauhan s/o Amar Chand, r/o Army Public School Dagshai, Tehsil and District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Ajay Chauhan to Ajay Kumar Chauhan. Please note.

AJAY KUMAR CHAUHAN
*s/o Sh. Amar Chand,
r/o Army Public School Dagshai,
Tehsil and District Solan (H.P.).*

